प्रेषक.

श्री राजेन्द्र कुमार, अपर सचिव. उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विमाग

देहराद्न : दिनांक 0 6 अयस्त 2013.

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत भटवाड़ी में एन.टी.पी.सी. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्ज साफ्ट से तिहार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.77 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन!

महोदय.

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 450/1जी-3338 (उ०का०) दिनांक 14-08-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत भटवाड़ी में एन.टी.पी.सी. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्ज साफ्ट से तिहार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.77 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मेंत्रालय के पत्र संख्या 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 174 / 2011 / एफ.सी. / 38 दिनांक 07-08-2013 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं :--

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. वन विमाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय प्र प्रत्यावर्तित मूमि के बदले ग्राम-तिहार, तहसील-भटवाड़ी, जिला-उत्तरकाशी में 9.54 हे0 अवनत सिथिल एवं सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के नागृदर्शी सिद्धान्तों 3.2(1) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।

3. वन विमाग के पक्ष में म्यूटेशन की गई उक्त भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा यथोचित प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विमाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कैम्प कार्यालय, एफ0आर0आई0 देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा

उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षिति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षिति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देख होगा।

6. जक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।

7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विमाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित व्यारोपण से 10 वर्षों तक रख-रङ्गव किया जायेगा।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई। से अनुपालन किया जायेगा।

- मा त्रपापणा प्रजन्मा द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
- 12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों / स्टाफ की रसोई गैस / किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
- 13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी प्रकार का
- 14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से निर्माण में
- 15. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित
- 16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत किया
- 17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
- 18. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को मारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर
- 19. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0-104/26/प्र0स0-आ0व0ग्रा0वि० दि०-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं0-110/26/प्र0स0-आ0व0ग्रा० वि० वि0-4-1-2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः ए-2-75/ दस-77-14(4) / 74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

मवदीय, (राजेन्द्र कुमार) अपर सचिव।

## संख्या:-जी0आई0:- 2784/ 7-1-2013-600(3715)/2011. दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1. अपर प्रमुख वन सरंक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कैम्प कार्यालय, 2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून। 5. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती। the a set of the set
- 6. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी
- 7. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
- 8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।
- 9 निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से